

संशोधित वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट आज अंतरिम निर्णय सुनायेगा

मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने लगातार सुनवाई के बाद 22 मई को आदेश सुरक्षित रखा था

नई दिल्ली, 14 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को तीन प्रमुख मुद्दों पर अपना अंतरिम फैसला सुनाएगा। इनमें एक मुद्दा यह है कि क्या वक्फ घोषित संपत्तियों को अदालतें वक्फ की सूची से हटा (डिनोटिफाई) सकती हैं या नहीं। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि क्या कोई संपत्ति उपयोग के आधार पर वक्फ (वक्फ बाय यूजर) या किसी दस्तावेज के जरिए वक्फ (वक्फ बाय डीड) घोषित की जा सकती है। ये सभी मुद्दे वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2०25 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उठे थे।

चीफ जस्टिस (सीजेआई) बीआर गवई की अध्यक्षता वाली

- इस केस में एक बड़ा मुद्दा यह है कि अगर किसी जमीन को पहले अदालत ने वक्फ घोषित कर दिया तो क्या सरकार बाद में उसे वक्फ की सूची से हटा सकती है।

बेंच ने 22 मई को इन तीनों पर दोनों पक्षों को दलीलों को सुना था, जिसके बाद अंतरिम अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। आदेश सुरक्षित रखने से शीर्ष कोर्ट की वेबसाइट पर 15 सितंबर की कार्य सूची के मुताबिक, कोर्ट सोमवार को इस मामले पर अपना आदेश सुनाएगा।इन मुद्दों में एक बड़ा मुद्दा यह है कि अगर किसी जमीन को पहले अदालत ने वक्फ घोषित कर दिया हो, तो क्या सरकार बाद में उसे वक्फ की सूची से हटा सकती है या नहीं। यह मामला वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 से जुड़ा है।

ने रोक लगाने की मांग की थी और जिन पर कोर्ट अब अंतरिम आदेश देने जा रही है।

याचिका दाखिल करने वालों ने डिनोटिफिकेशन के मुद्दे के अलावा राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के ढाँचे पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इन संस्थाओं को सिर्फ मुसलमानों द्वारा ही चलाया जाना चाहिए, सिर्फ वे लोग छोड़कर जो अपने सरकारी पद की वजह से अपने-आप सदस्य बनते हैं। तीसरा मुद्दा एक ऐसे प्रावधान से जुड़ा है, जिसमें कहा गया है कि यदि जिला कलेक्टर यह जांच कर रहा हो कि कोई संपत्ति सरकारी जमीन है या नहीं, तो उस समय उस संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा।

- नवरात्रि के दौरान निर्बाध तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त बैठक।

रहें। 26 अगस्त को अथकुवारी में इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भारी बारिश से आये भूस्खलन में कम से कम 34 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसमें अधिकतर श्रद्धालु थे और कई अन्य घायल हो गये थे। कटरा के आध्यात्मिक विकास केंद्र में 13 सितंबर को श्री माता वैष्णो देवी मंदिर बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन कुमार वैश्य की अध्यक्षता में एक संयुक्त बैठक की गयी, जिसमें 22 सितंबर से चलने वाली नौ दिनों तक चलने वाले नवरात्रि के दौरान निर्बाध तीर्थयात्रा सुनिश्चित करने पर चर्चा की गयी। वैश्य ने कहा कि नवरात्रि निकट है और ऐसे में बोर्ड को तीर्थस्थल और कटरा स्थित आधार शिविर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है इसलिए नवरात्रि पर्व के दौरान सभी एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करें। उन्होंने आने वाले दिनों में बिना किसी परेशानी के तीर्थयात्रा के लिए विभिन्न मोर्चों पर कार्रवाई करने का भी आह्वान किया।

डिवाइडर से टकरा कर रिंग रोड से कार नीचे गिरी, सात की मौत

हरिद्वार में अस्थी विसर्जन कर लौटते समय कार सवारों के साथ यह हादसा हुआ

जयपुर, 14 सितंबर। शिवदासपुरा थाना इलाके में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रिंग रोड से नीचे गिर गई। हादसे में कार में सवार दो परिवार के सात लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दो बच्चे और दो महिलाएं भी शामिल हैं। हादसा थाना इलाके में प्रहलादपुरा के पास शनिवार देर रात हुआ।

- शिवदासपुरा थाना इलाके में प्रहलादपुरा के पास अंडर पास के पानी में उलटी पड़ी कार को पुलिस ने क्रेन से बाहर निकाला तो कार में सवार सातों मृत पाये गये।

(36) और बेटे रुद्र (14 महीने) और फुलियाकांठ (भीलवाड़ा) निवासी उनके रिश्तेदार अशोक वैष्णव उर्फ कालुराम (47), उनकी पत्नी सीमा देवी (45), बेटे रोहित (23) और पोते गजराज (3) की मौत हो गई। हादसे में मारे गए सभी लोग हरिद्वार में अस्थियां विसर्जन करके घर लौट रहे थे। थानाधिकारी सुरेंद्र सैनी ने बताया कि शिवदासपुरा इलाके में प्रहलादपुरा के पास रिंग रोड पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई और रिंग रोड से 16 फीट नीचे अंडरपास में भरे पानी में गिर गई। पुलिस ने बताया कि रिंग रोड पर डिवाइडर के बीच करीब 20 फीट खाली जगह है। इसके बीच में से कार नीचे पानी में गिरी थी। हादसा इतना भीषण था कि सभी की मौके पर ही मौत हो गई।

सुरेन्द्र सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। प्रार्थमिक जांच में सामने आया है कि रिंग रोड से नीचे अंडरपास में भारी जलभराव के कारण कार नाले में पलट गई। एसीपी चाकसू सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि वाटिका सांगानेर निवासी रामराज वैष्णव (38), पत्नी मधु

बीस सीटें नहीं दीं, तो 1०० सीटों पर चुनाव लड़ेंगे

केन्द्र सरकार में मंत्री जीतनराम मांझी की घोषणा ने एनडीए में खलबली मचाई

गयाजी, 14 सितंबर। केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के मंत्री और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (सेब्युलर) के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है। लोकसभा चुनाव के कुछ समय पहले महागठबंधन से निकल कर एनडीए में लौटे जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है। मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी को अगर 2० सीटों पर मौका नहीं दिया गया तो वह 100 प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे।

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि वह एनडीए के प्रति समर्पित हैं और लोकसभा चुनाव में भी हर बात स्वीकार की थी। इस गठबंधन में प्रतिष्ठा मिली है, लेकिन हमारे मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की भी कुछ उम्मीदें हैं। यह उम्मीदें पूरी करने का बिहार विधानसभा चुनाव एक मौका है और हम एनडीए को जिताने के लिए हर तरह

- मांझी ने कहा कि वे चाहते हैं, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा हर हाल में बिहार में मान्यता प्राप्त दल बने। इसके लिए विधानसभा में 8 सीटें या कुल मतदान का 6 प्रतिशत वोट चाहिए।

से ताकत झोंकने को तैयार भी हैं। लेकिन, इस बार चुनाव में एनडीए के अंदर हमें बिहार की 20 सीटें चाहिए। हमने यह मांग रखी है। बात कर रहे हैं। लेकिन, अगर बात नहीं बनी तो 1०0 सीटों पर भी प्रत्याशी उतार सकते हैं। मांझी ने कहा कि अगर मान लिया जाए हमको हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अधिकृत करता है, तो हम जरूर फैसला लेंगे। फैसला में हमारा एक ही चीज है कि हम चाहते हैं, हमारा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हर हालत में मान्यता प्राप्त कर ले। मान्यता प्राप्त करने के लिए हमको 8 सीट विधानसभा में चाहिए या पोलिंग का 6 प्रतिशत टोटल वोट चाहिए। हमारे साथ दो परिस्थिति हैं। आठ सीट जीतने के लिए हमको काम

से कम 15 से 20 सीट मिलेगा तभी ना हम इस दायरे में आ सकते हैं। हम सभी सीट तो जीत जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। अगर 60 प्रतिशत स्कोरिंग सीट माना जाए तो भी कहा जाएगा। तब 15 सीट की बात आती है। अगर 15 सीट हमको मिलेगा और 8 सीट जीत जाएंगे तो एक प्रावधान यह है। नहीं तो हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। बिहार में हर जगह हमारा दस हजार और 15 हजार वोटर है। जीत करके 6 प्रतिशत हम वोट ले आएंगे और हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। दस वर्ष साक्षरता सचिव और उच्च शिक्षा सचिव के रूप में कार्यरत हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय में सामाजिक क्षेत्र से संबंधित मामलों को संभाल रहे हैं। खरे ने केंद्र और राज्य सरकारों में कई प्रमुख पदों पर भी कार्य किया है।

अमित खरे को 31 मई 2018 को भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण सचिव के पद पर नियुक्त हुए और इसके बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव और उच्च शिक्षा सचिव के रूप में कार्य किया। खरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को तैयार करने और लागू करने वाली मुख्य टीम का हिस्सा थे।

- वर्तमान में वे प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं।

अनुबंध के आधार पर होगी। खरे की छवि एक ईमानदार अधिकारी की रही है और उन्हें चार घोटाले का पर्दाफाश करने में उनकी भूमिका के लिए भी जाना जाता है। इस नियुक्ति से पहले खरे 12 अक्टूबर 2021 से प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय में सामाजिक क्षेत्र से संबंधित मामलों को संभाल रहे हैं। खरे ने केंद्र और राज्य सरकारों में कई प्रमुख पदों पर भी कार्य किया है।

मराठा आरक्षण के विरोध में ओबीसी-बंजारा व आदिवासी एकजुट हुए

मराठा समुदाय को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने से अनुसूचित जाति-जनजाति व ओबीसी वर्ग चिन्तित

जालना, 14 सितंबर। महाराष्ट्र में अब मराठा आरक्षण का विरोध तेज हो गया है। मराठों को आरक्षण देने के लिए जारी सरकारी आदेश के विरोध में जालना जिले में ओबीसी-बंजारा और आदिवासी संगठन ने विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। संगठनों का कहना है कि राज्य सरकार जब तक मराठा आरक्षण गवर्नमेंट रैजोल्यूशन (जी.आर.)को वापस नहीं लेती, तब तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

- धाराशिव निवासी बंजारा स्नातक ने शनिवार को एसटी आरक्षण की मांग पर आत्महत्या की। ओबीसी नेताओं ने 10 अक्टूबर को नागपुर में एक विशाल मोर्चा निकालने का संकल्प लिया है।

अध्यक्ष संदेश चव्हाण ने कहा कि हमें अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था और हैदराबाद राज्य में आरक्षण प्राप्त था। हम चाहते हैं कि हमारे समान अधिकार बहाल हों। धाराशिव निवासी 32 वर्षीय बंजारा स्नातक ने शनिवार को आत्महत्या कर ली। उसने अपने पिछे एसटी आरक्षण की मांग करते हुए एक नोट छोड़ा था। म्याहार सितंबर से बंजारा युवा जालना कलेक्टर कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। जबकि वरिष्ठ नेता हरिभाऊ राठोड़ ने 15 सितंबर को जालना और बीड में मार्च

समन्वयक संजय लाखे पाटिल ने भी जारंगे के खिलाफ बोलते हुए दावा किया है कि उन्हें हैदराबाद राजपत्र के बारे में कोई गहन जानकारी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल कुनबी रिकॉर्ड वाले मराठों को ही लाभ मिलेगा। सरकार मराठों को धोखा दे रही है।

मराठवाड़ा क्षेत्र हैदराबाद के निजाम के अधीन था। उनके प्रशासन ने राजपत्र में जातियों और व्यवसायों का दस्तावेजीकरण किया था। 1918 में मराठों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया गया था। पर था, जिनमें से पांच, औरंगाबाद, बीड, नांदेड़, परभणी और उस्मानाबाद, बाद में महाराष्ट्र का हिस्सा बन गए।

नाकालने की घोषणा की है। आदिवासी संगठनों ने बंजारा समुदाय की मांग का विरोध किया है और दावा किया है कि बंजारा समुदाय को विमुक्त जाति और घुमंतु जनजाति (बीजेएनटी) खंड के तहत पहले से ही 3 प्रतिशत कोटा का लाभ मिल रहा है। ओबीसी कार्यकर्ता नवनाथ वाघमारे और सतसुंग मुंधे ने चेतावनी दी कि आरक्षण बंद ने से ओबीसी श्रेणी में पहले से सूचीबद्ध 374 जातियों के अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे। ओबीसी नेताओं ने 1० अक्तूबर को नागपुर में एक विशाल मोर्चा निकालने का संकल्प लिया है। वहीं मराठा क्रांति मोर्चा के राज्य

‘संगीतकार इलैयाराजा को भारत रत्न दें’

चेन्नई, 14 सितंबर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने केंद्र सरकार से महान संगीतकार इलैयाराजा को भारत रत्न से सम्मानित करने का आग्रह किया है।

राज्य सरकार द्वारा रविवार को चेन्नई में आयोजित भव्य सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा “मैं यह अनुरोध केवल फिल्म उद्योग में इलैयाराजा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा तमिलनाडु

- मुख्यमंत्री स्टालिन ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया।

के लोगों की ओर से भी नहीं, बल्कि विश्व भर में उनके प्रशंसकों की ओर से भी कर रहा हूँ।”

उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार संगीत के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले युवा संगीतकारों के लिए उनके नाम पर एक वार्षिक अवार्ड “इसैनानी इलैयाराजा पुरस्कार” देगी। संगीतकार की महानता को याद करते हुये मुख्यमंत्री ने जिक्र करते हुए कहा कि वे इलैयाराजा के लंदन दौरे से पहले उनके घर उन्हें सम्मानित करने गये थे। गौरतलब है इलैयाराजा ने लंदन के प्रसिद्ध रॉयल फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा में अपनी प्रस्तुति दी थी। उन्होंने कहा ” आम तौर पर मुख्यमंत्री से अनुरोध किया जाता है। लेकिन मैं इलैयाराजा से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे संगम की शास्त्रीय रचनाओं को संगीत के माध्यम से जीवित करें। इससे इन प्राचीन कृतियों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।” इस अवसर पर अभिनेता रजनीकांत और कमल हासन के साथ-साथ उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने संगीतकार इलैयाराजा की प्रशंसा की, जिन्होंने इस अवसर पर एक संगीत प्रस्तुत दी।

सेमीकंडक्टर, बायोएथनॉल तथा ईंधन संयंत्रों से असम का विकास होगा : मोदी

प्रधानमंत्री ने रिफायनरी संयंत्र के उद्घाटन के बाद विशाल जनसभा को संबोधित किया

- प्रधानमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार, हमारे समुद्री क्षेत्र में ईंधन का भंडार है और उसके दोहन के लिए हम तेजी से कदम उठा रहे हैं।
- मोदी ने कहा कि वाराणसी के बाबा विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तरह माता कामाख्या मंदिर का कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है।

बनाया जा रहा है। मोदी ने कहा कि जैसे-जैसे भारत तेजी से विकसित हो रहा है उसके लिए गैस, बिजली, ईंधन की जरूरत बढ़ेगी। इसलिए हम अब ईंधन क्षेत्र में और स्वच्छ ऊर्जा के लिए अपने सामर्थ्य को नई दिशा दे रहे हैं। हमारे समुद्री क्षेत्र में विशेषज्ञों के अनुसार ईंधन का भंडार तेजी से आगे बढ़े हैं और हम दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि असम में जो बायोएथनॉल संयंत्र लगाया गया है उससे यहां किसानों को फायदा होगा और किसानों को खेती करने में मदद मिलेगी। उनका कहना था कि असम में जो बायोएथनॉल संयंत्र लगाया गया है उससे यहां किसानों को फायदा होगा और किसानों को खेती करने में मदद मिलेगी। उनका कहना था कि असम में

हर साल 200 करोड़ रुपए किसानों के हित में खर्च किये जाएंगे। उन्होंने कामाख्या मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि माता कामाख्या के मंदिर में कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। यह कॉरिडोर ठीक उसी तरह से होगा जैसा वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। इससे श्रद्धालुओं को माता के दर्शन में आसानी होगी। पॉलीप्रोपाइलीन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे प्लास्टिक का सामान बनता है जो हर घर में इस्तेमाल होता है। केंद्र सरकार ने असम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोलाघाट में पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र बनाया जा रहा है जिससे आधुनिक तकनीकी से इसका

यहां निर्माण होगा। मोदी ने गोलाघाट में

असम में 5.8 तीव्रता का भूकंप आया

नई दिल्ली, 14 सितंबर। असम के उदलपुरी में रिक्टर पैमाने पर 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के डर से लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर निकल गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) ने यह जानकारी दी। एनसीएस के मुताबिक, भूकंप रविवार शाम 4 बजकर 41 मिनट पर आया और इसका केंद्र 5 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप के बाद गुवाहाटी में लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। अब तक कहीं से

- रविवार शाम 4:40 बजे आये भूकंप में कोई जान-माल का नुकसान नहीं हुआ।

जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि, कई मकानों में दरारें आ गई हैं। एनसीएस के मुताबिक भूकंप के झटके असम के साथ-साथ बंगाल और भूटान में भी महसूस किए गए हैं।

कांस्टेबल भर्ती : भतीजे की जगह परीक्षा देने पहुँचा चाचा गिरफ्तार

जयपुर, 14 सितंबर। मुरलीपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती-2025, के तहत एक डमी कैंडिडेट को गिरफ्तार किया है, जो अपने भतीजे की जगह पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर देने पहुंचा था। आरोपी बायोमेट्रिक जांच के दौरान पकड़ा गया। आरोपी चाचा भूपेंद्र और भतीजे धर्मवीर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अपने भतीजे की जगह डमी कैंडिडेट बनकर पहले भी कई प्रतियोगिता परीक्षा दे चुका है। पुलिस आरोपी से

- पुलिस जाँच के अनुसार, आरोपी अपने भतीजे की जगह पहले भी कई प्रतियोगी परीक्षा दे चुका है।

पूछताछ कर रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम) ने बताया कि मुरलीपुरा के शहीद हिम्मत सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का परीक्षा सेंटर था। जिसमें आरोपी भूपेंद्र गुर्जर का रोल नंबर व सेंटर कोड व सेंटर का नाम सहित बायोमेट्रिक कैचर व फोटो पाया गया। बायोमेट्रिक में पाया गया कि वह महावीर वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित परीक्षा में अन्य नाम से सम्मिलित हुआ है। इसके बाद भूपेन्द्र से पूछताछ की गई। तकनीकी सहायता से 1 जून-2025 को अपनी बायोमेट्रिक अपने भतीजे धर्मवीर के नाम पर प्री डी एल एड (डिप्लोमा इन फैमिलिरी एजुकेशन) परीक्षा में यूज की थी। भतीजे की जगह डमी कैंडिडेट बैठकर उसको प्रतियोगिता परीक्षा पास करवाई थी। जिससे धर्मवीर बिना परीक्षा के ही वर्तमान में केबीएम टीचर ट्रेनिंग कालेज बोली सवाई माधोपुर में बेसिक स्कूल ट्रेनिंग कोर्स कर रहा है।